भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 476
03 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

सेलम इस्पात संयंत्र से जुड़ी चिंताएँ

476. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का आधार बने सेलम इस्पात संयंत्र के संभावित रणनीतिक विनिवेश या इसमें व्याप्त गतिरोध से संबंधित चिंताओं पर विचार किया है;
(ख) क्या हाल के वर्षों में सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए कोई निधि आवंटित की गई है;
(ग) राज्य की उत्पादन क्षमता के बावजूद, जेएसडब्ल्यू-सेल सहयोग सहित संयुक्त उद्यम या विस्तार प्रस्तावों में तमिलनाडु को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत तमिलनाडु स्थित इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं; और
(ङ) इस्पात क्षेत्र के निवेश का समान क्षेत्रीय वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क)और(ख): सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सेलम के रणनीतिक विनिवेश के संबंध में विनिवेश संबंधी सचिवों के मुख्य समूह (सीजीडी) की सिफारिशों के आधार पर, वैकल्पिक तंत्र (ए एम) ने दिनांक 04.07.2019 को सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सेलम के रणनीतिक विनिवेश के लिए जारी मौजूदा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को, चयनित बोलीदाताओं की रुचि की कमी के कारण, रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने दिनांक 01.06.2022 को मंत्रिमंडल के 18.05.2022 के निर्णय से अवगत कराया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के बोर्डों को अपनी इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश के लिए लेन-देन करने का अधिकार दिया गया है, जहाँ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने सेलम इस्पात संयंत्र की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विद्युत, ईंधन, जनशक्ति, धातु पुनर्प्राप्ति तथा उत्पादन के क्षेत्रों में प्रचालनात्मक सुधार किया है।

(ग) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका तमिलनाडु सहित देश में इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करके इस्पात उद्योग को सुविधा प्रदान करने की है। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन पूरे देश में समान रूप से लागू है।

******